DR. NAGEN SAIKIA: Madam, I want to seek one clarification.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think he gave a very elaborate reply. I doubt if he has left any point. You can go and talk to the Minister in the Lobby.

DR. NAGEN SAIKIA: Madam, through you, I want to ask only one question. May I know from the Minister whether he would take any steps against the *Surya* magazine where some allegations have been made against the Home Ministry.

SHRI SANTOSH MOHAN DEV: Madam, we are strong believers of the freedom of the press. If we have to go like that then we will find hundreds of cases. You know very well that the Press is not very happy and he does not know the background of *Surya* magazine as we know.

Modernisation of steel plants in public sector

उपसभापति : राम अवधेश जी, आप पहले अनुमति लीजिए कि आप को आगे से बोलना है ।

श्री राम अवधेश सिंह : (बिहार) : महोदया, मुझको अनुमति दी जाय ।

उपसभापति : आप अपनी सीट से क्यों नहीं बोल रहे हैं ?

श्री राम अवधेश सिंह : मेरे सब नोट्स वगैरह यहां रखे हैं ।

उपसभापति : इस शर्त पर आपको हम अनुमति देते हैं कि आप पन्द्रह मिनिट में बोलेंगे सिर्फ, जो कि आपका टाइम है । अगर आप पन्द्रह मिनिट में बोलें तो बोलिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : पन्द्रह मिनिट में तो नहीं होगा ।

उपसभापति : पन्द्रह मिनिट से ज्यादा टाइम नहीं है ।

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : मेडम डिप्टी चेयरमैन, अगर पन्द्रह मिनिट में यह स्पीच खतम नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा कि मैं चला जाने वाला हूं । आप ज्यादा समय लेंगे तो मैं बैठने वाला नहीं हूं ।

श्री राम अवधेश सिंह : : नहीं, ऐसा मत कहिए ।

उपसभापति : हम भी चले जाएंगे, हम सब लोग चले जाएंगे, हाउस एडजोर्न करके ।

श्री राम अवधेश सिंह : आप तो नहीं जाइएगा ।

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : मैं अपना समय इनको दे देता हूं, इनको बोलने दीजिए, जितनी देर बोलना है ।

उपसभापति : अभी आप बोलिए नहीं, खाली मंत्री जी का ध्यान खींचिए । अभी आप खाली नोट से पढ़ दीजिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : माननीय उपसभापति महोदया, आप सचमुच दिल से . . .

उपसभापति : नहीं, खाली नोट से पढ़िए । फिर मंत्री जी बोलेंगे ।

श्री राम अवधेश सिंह : माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से प्रौद्योगिक परिवर्तनों और उनमें अंतर्ग्रस्त लागत के आधार पर सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता के संबंध में इस्पात और खान मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): Madam, you will excuse me, I would like to reply in English.

श्री राम अवधेश सिंह : नहीं, हमको हिन्दी में उत्तर दीजिए ।

उपसभापति : आप वह लगा लीजिए आला, ट्रांसलेशन का ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं कुछ कुछ समझता हूं इंगलिश, लेकिन इनको हिंदी में बोलना चाहिए ।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: Madam, Hon'ble Members are aware that over the past 20—30 years our public sector steel plants have lapsed into technological obsolescence because of outdated machinery and equipment. This has resulted in uncompetitive cost and poor quality of production as compared to international norms. The energy consumption is also high. The profitability of the steel plants has thus gone down as a consequence of their obsolescence.

Government proposes to rectify this situation by introduction of the state-of-the-art technology into the public sector steel plants. The steel plants presently planned to be modernised are Durgapur Steel Plant, Rourkela Steel Plant and the Burnpur Works of the Indian Iron and Steel Company.

The rationale for the modernisation of the Public Sector steel plants is to clear the backlog in maintenance and upgrade tchnology so as to fully exploit the existing assets in the steel plants. These efforts are meant to provide better service to Indian customers through better quality steel at competitive prices. The investments will ensure cost reduction through energy saving and improved productivity and will also upgrade the total quality of operations.

Considerable work as already been done in this modernisation programme. In the case of Durgapur Steel Plant, the definitive cost estimates have been approved and almost all the contracts for the major turn-key packages have been awarded. For Rourkela Steel Plant, Government have approved Phase-I of the modernisation project. In the case of IISCO, basic engineering studies are underway, and the preparation of a Detailed Project Report has also started.

The thrust in this modernisation Programme is to employ indigenously available skills and expertise to the fullest and also to procure whatever equipment can be manufactured from within the country making the time schedule Import content is confined to design and supply in respect of state-of-the-art technology and equipment which are not, yet available in India. The import content is likely to be to the region of 20—35 per cent of the total cost of the programmes in each of the steel plants.

The total estimated cost of the modernisation programme to be incurred over the next 5 years or so is around Rs. 10,000 crores. Out of this the estimate sanctioned by Government for Durgapur is Rs. 2,667 crores. The estimated cost for Rourkela is Rs. 2,460 crores, which is being processed for a firm investment decision. The IISCO moderniation plan is likely to cost around Rs. 3,000 crores. In addition to this, about Rs. 1100 crores is likely to be spent on upgrading the production facilities at Bokaro.

उपसभापति : राम अवधेश जी, आप 15 मिनट बोलेंगे ।

श्री राम अवधेश सिंह : : 15 मिनट में तो नहीं होगा।

उपसभापति : 10,000 करोड़ का है तो 10 मिनट बोलिए ।

श्री राम अवधेश सिंह :: माननीय उपसभापति महोदया, मैं सचमुच दिल से आभारी हूं आपके प्रति और इस सदन के अध्यक्ष के प्रति कि जिन्होंने कृपा करके देश के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन और सरकार तथा जनता का ध्यान खींचने की अनुमति दी । इस विषय पर तो चर्चा बहुत गंभीर रूप से होनी चाहिए थी और लम्बी होनी चाहिए थी . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री बी० सत्यानारायण रेड्डी : सारी रात पड़ी हुई है, बोलिए। . . . (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : लेकिन सत्र के अंत में और अंतिम घंटे में इस पर चर्चा हो रही है, इसलिए काफी सदस्य हैं नहीं, लेकिन जिस विषय की ओर मैं ध्यान खींचना चाहता हूं, वह विषय बहुत गंभीर है।

महोदया, किसी मुल्क के लिए इस्पात का क्या महत्व है, यह किसी से छिपा नहीं है। डा० लोहिया कहा करते थे कि किसी भी देश की खुशहाली मापने के दो यंत्र हैं। . . . एक का

8 P. M. नाम है स्टील और दूसरे का नाम है दूध प्रति व्यक्ति कितनी खपत दूध की होती है उससे अंदाजा लगता है कि कृषि की कितनी उन्नति है मुल्क में और प्रति व्यक्ति इस्पात की कितनी खपत है इससे उस देश के औद्योगीकरण का पता चलता है। देश के औद्योगीकरण के महत्व को समझते हुए समाजवाद लाने की दिशा में बढ़ने के लिए इस्पात का उत्पादन आवश्यक है। इस बात को समझकर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात के कारखाने लगाने का फैसला किया था और चाहा था अपनी इंडस्ट्रियल पालिसी में कि जितने की सेक्टर हैं, खासकर हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज वे सारे के सारे पब्लिक सैक्टर में बनाए जाएं और अपने जीवन पर्यन्त समाजवाद को लाने के लिए उन्होंने कोशिश भी की और चाहा कि इस्पात के क्षेत्र से, ऊर्जा के क्षेत्र से निजी उद्योगपतियों को हटाया जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके सपनों को उनके तथाकथित उत्तराधिकारी आज उसका नाम लेते अघाते नहीं हैं, रात-दिन और जब कभी जरूरत पड़ती है तो जवाहर लाल जी का नाम लेते हैं, लेकिन उनके सपनों को चकनाचूर करने में कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। जब तक कुमारमंगलम इस्पात मंत्री थे तब तक इस दिशा में कार्यवाही होती रही और समाजवाद को आगे थोड़ा-थोड़ा खिसकाने में मदद की, लेकिन बाद के इस्पात मंत्रियों ने बहुत गैर जिम्मेदारी से काम किया और देश में इस्पात के उत्पादन को जान-बूझकर निजी क्षेत्र के लोगों से मिलकर, लंबी, गहरी साजिश के तहत इस्पात उत्पादन को धक्का दिया और इस तरह से धक्का दिया जिसकी मिसाल नहीं है।

महोदया, मंत्री जी ने जो बयान दिया वह बिलकुल अधूरा है, उसमें कुछ है नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माडर्नाइजेशन की आवश्यकता के बारे में जितनी बातें मंत्री जी ने कही हैं, उनसे और भी ज्यादा कही जा सकती हैं, इस लिए हम कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। आवश्यकता है, उसका आधुनिकीकरण होना चाहिए, इसमें कौन रोकता है ? लेकिन जिस ढंग से आप आधुनिकीकरण करते हैं, जिस तरह से आपने फिगर दी, वह संदेहास्पद है, संदेह के घेरे में है क्योंकि जो आपने पब्लिक सैक्टर बनाए, जैसे मैकान है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फार आयरन एंड स्टील की स्थापना 1973 में इस उद्देश्य से की गई थी कि आगे जब भी इस देश में माडर्नाइजेशन का काम होगा तो आर० एंड डी० अपने तकनीकी ज्ञान से खोज और विकास की नई चीजें लाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यह कहा गया था कि 10 साल के बाद बाहर से एक भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो टेक्निकल नोहाऊ इनके पास प्राप्त हो जाएगा वह पर्याप्त होगा देश के स्टील प्लांट को माडर्नाइज करने के लिए। मैकान है। मेकान रांची में बहुत बड़ी प्रयोगशाला है डिजाइन के इंजीनियर्स हैं, बड़ा लम्बा-चौड़ा आफिस है। उसकी इतनी क्षमता है कि एक साथ दो स्टील प्लांट के डिजाइन कर सकता है। बाहर के देशों में यानी मिडिल ईस्ट में और अफ्रीकन के कुछ देशों में वह काम लेते हैं, उनका डिजाइन स्वीकार होता है। लेकिन जब दुर्गापुर प्लांट का डिजाइन मैकन ने किया तो उसका ओरीजनल डिजाइन 900 करोड़ रुपये का दिया था। 900 करोड़ रुपये में एक मीलियन टन स्टील का प्लांट होगा।

फिर उसमें बढ़ोतरी हुई तो 1360 करोड़ रुपये का डिजाइन दिया और उसने कहा कि 50 छोटे-छोटे पैकेज में इसका काम किया जायेगा ताकि देश के विभिन्न सेक्टर के छोटे-छोटे संस्थान हैं उनका सहयोग लिया जाए और उनकी मशीनरी, उनके इक्युपमेंट काम में लाये जायें लेकिन उसको नहीं माना गया और कुछ डिजाइन में चेंज करने के ख्याल से यानी इस बहाने से उसको 2667 करोड़ रुपये का बनाया गया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जो करीब-करीब 1660 या 1668 करोड़ रुपये बताये गये, 1660–1668 करोड़ रुपये का काम विदेशी कम्पनियां करें जैसे कि जर्मनी की कंसाटियम मल्टीनेशनल कम्पनीज करेंगी इसी तरह इसमें रूस की भी कम्पनी है यू०एस०एस०आर० की टी०पी०ई० है और वेस्ट जर्मनी की दिमाल। बिरला की टेक्नोलोजिकल सर्विस कम्पनी है इसके पास कितना स्टाफ है मैं यह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह बिरला टेक्नीकल सर्विस क्या है और इसके पास कितना स्टाफ है और यह कितने डिजाइन कर सकती है? इनको 461 करोड़ रुपये के बजाय 1668 करोड़ में दिया गया। हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर की कम्पनीज हैं वह बिरला जी के पास जायेंगी कि हम को काम दे दिया जाए, हम आपका काम कर देंगी। होना यह चाहिए था कि बिरला जी में अगर क्षमता होती करने की, टेक्नीकल सलाह देने की तो वह खुद जाते और कहते कि हम आपका सहयोग करना चाहते हैं लेकिन गाड़ी को रिवर्स कर दिया स्टील मंत्री ने। वह कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर को कि जायें प्राइवेट सेक्टर के पास। उनके सामने नाक रगड़वाते हैं काम के लिए। पब्लिक सेक्टर में भारी-भारी कम्पनियां हैं, भारी उद्योग हैं। क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो मैं नाम बता सकता था। 252–253 कम्पनियां हैं पब्लिक सेक्टर में। मेरा कहना यह है कि जब आपके पास पब्लिक सेक्टर मौजूद है उससे आप काम ले सकते हैं तो फिर प्राइवेट सेक्टर की विदेशी कम्पनियों से क्यों लेते हैं आखिर इसका कारण क्या है? टिस्को ने अपने कारखाने का मॉडर्नाइजेशन किया और दो मिलियन टन से तीन मिलियन टन का उत्पादन उसने किया और उसका खर्चा एक हजार करोड़ रुपये हुआ। एक हजार करोड़ रुपए में एक मिलियन टन बढ़ा। मैं दुर्गापुर की बात बताता हूं। सन् 1953 से 1960 तक जब दुर्गापुर बना तो उसकी एक मिलियन टन की क्षमता थी और उसके बाद 1965 से 1970 तक उसका एक्सपेंशन हुआ तो उसकी क्षमता 1.6 मिलियन टन हो गई। लेकिन रेटेड केपिसिटी से बहुत कम उत्पादन होता है। 6 मिलियन टन उत्पादन होता था। रेटेड केपेसिटी इतनी कम है, फिर भी उसमें 2667 करोड़ रुपये लगाते हैं। इसके बाद भी उसकी असली उत्पादन क्षमता 1.6 मिलियन के आस-पास ही रहती है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए।]

उसकी क्षमता ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वह 8.9 तक ही सीमित है। इसलिए रेटेड केपेसिटी पर वह कभी गया नहीं। 2668 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी 7.8 मिलियन टन ही बढ़ाते हैं। वहीं आपकी बगल में जो प्राइवेट सेक्टर की कम्पनी है टिस्को, वह देशी सामान, देशी मशीनों और इक्विपमेंट से मोडर्नाइजेशन करती है तो एक हजार करोड़ रुपयों में एक मिलियन का बढ़ाती है तो आखिर आपको विदेशी कम्पनियों से मोडर्नाइजेशन का काम लेने से क्या फायदा है? इसका क्या राज है? इसमें जरूर गहरी साजिश है और गहरा राज है। आप जितना समझाना चाहें, अपने ढंग से फीगर्स को उलट-पलट कर दे सकते हैं। लेकिन इस बात को नहीं समझा सकते हैं कि अपने ही देश में, अपने बगल में, एक कम्पनी एक हजार करोड़ रुपये में एक मिलियन टन स्टील पैदा करने की क्षमता बढ़ा देती है और आप 26 सौ करोड़ रुपये से ऊपर लगाकर भी .8 मिलियन टन उत्पादन करते हैं। ठीक इसी तरह से आपने राऊरकेला के फीगर दिये

[श्री फी० सत्यनारायण रेड्डी]

हैं 2460... (व्यवधान) । ऐसो बहस में तो कभी पार्टी से ऊपर उठ जाया करो। इसके बाद आप भी बोलेंगे। राउरकेला की 1.9 मिलियन टन रेटेड केपेसिटी थी, लेकिन उसका उत्पादन 1.2 मिलियन टन होता था। उस पर आप 2460 करोड़ रुपये खर्च करते हैं और दो मिलियन टन पर ले जाना चाहते हैं।

[उपसभापति महोदय पीठासीन हुईं]

.8 मिलियन टन बढ़ाते हैं और वह भी ढाई करोड़ खर्च करके। इसका आखिर राज क्या है? आपकी बगल में एक हजार करोड़ पर एक मिलियन टन बढ़ाते हैं, लेकिन आप ढाई हजार करोड़ पर क्या करते हैं? राउरकेला के बारे में मुझे बताया गया है कि दस्तूर कम्पनी ने उसका डिजाइन किया। उसी दस्तूर कम्पनी ने टिस्को का डिजाइन किया। दस्तूर कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है तो जब वह एक प्राइवेट कम्पनी का डिजाइन बनाती है तो वह एक हजार करोड़ रुपये में और पब्लिक सेक्टर का कम्पनी का डिजाइन करते हैं तो वह ढाई हजार करोड़ रुपये में और उसमें उत्पादन भी कम होता है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? फिर बर्नपुर के बारे में हिसाब बताया गया है तीन हजार करोड़ रुपये का। यह बात सही है, लेकिन मुझ को बताया गया है कि इससे ज्यादा पैसा वहां पर खर्च कर रहे हैं एक जापान के कंजोर-डियम को देकर। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप विदेशी कम्पनियों का कंजोरडियम बनाकर इस्पात उद्योग का आधुनिकीकरण कर सकते हैं तो फिर जो हिन्दुस्तानी देशी कंपनियां पब्लिक सेक्टर में हैं, जो इस काम के लिए बनाई गई हैं उनसे क्यों नहीं आप भरपूर सहायता लेते। आप केवल वह चीज खरीदिये, जैसे कोई लेटेस्ट टेक्नोलाजी इलेक्ट्रोनिक्स में है, जिसके बिना काम ही न चलता हो, जो टेक्नालाजी दुनिया में कहीं और न मिलती हो अगर उसको आप खरीदते तो उसमें हम लोग समझ सकते थे कि आपकी लाचारी है और इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन यह काम भी आपने नहीं किया। हम लोगों की कंपनी मैकोन ने डिजाइन किया राजस्थान में अजर कोटा स्टील प्लांट का, ग्रीन लैंड में, जहां रोड नहीं है, पानी नहीं है, घर नहीं है द्वार नहीं है उन्होंने उसको बनाकर और सारी चीजों को ठीक करके तीन हजार करोड़ में दिया और एक मिलियन टन का उत्पादन दे रहा है। आप ढाई करोड़ रुपया, तीन करोड़ रुपया लगा देते हैं माडर्नाइजेशन में जबकि सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है और वह एक मिलियन टन भी उत्पादन नहीं करता है। उसको जब हमारे यहां के लोग कर सकते हैं तो आप उनसे क्यों नहीं करवाते? मैं आपको बताऊं कि आपके स्टील अथारिटी आफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं श्री वी० कृष्णामूर्ति, वे बहुत काबिल आदमी हैं और माहिर आदमी हैं। वे इतने माहिर हैं कि उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन होता रहता है। अभी वे मारुति लि० के भी सी०एम०डी० हैं। पता नहीं... (समय की घंटी)...ऐसा मत करिये अभी शुरूआत की है।

उपसभापति : 18 मिनट हो गए आपके।

श्री राम अवधेश सिंह : 18 मिनट नहीं 45 मिनट बोलना है मुझे।

उपसभापति : 45 मिनट नहीं बोलना है। मैं हाउस एडर्जन कर दूंगी।.. **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह : देसाई साहब आप ज्यादा ध्यान से सुनिये। आप पब्लिक सेक्टर के पक्ष के आदमी हैं, यह मैं जानता हूं।

तो महोदया, मैं यह कह रहा था कि एक अघोषित युद्ध इस्पात के क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है। शुरू के दिनों में जब पब्लिक सेक्टर में इस्पात के कारखाने लगने लगे तो टाटा ने बहुत हल्ला मचाया कि हमारा ही लोहा और इस्पात नहीं बिकता है तो क्या भारत सरकार पागल हो गई है तो इतने कारखाने खोल रही है। लेकिन जब इन कारखानों का स्टील भी कम पड़ने लगा

फिर वह अपना एक्सपेंशन मांगने लगा कि हमें भी एक्सपेंशन की स्वीकृति दे दो। इस एक्सपेंशन की इजाजत उनको बहुत परेशानी के बाद मिली। पहले पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच शीत युद्ध चल रहा था, बहुत दिनों से लेकिन अब यह खुल्लमखुल्ला युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया है। दस्तूर कंपनी और टिस्को ये सब मिलकर अपने लोगों को पब्लिक सेक्टर में, मेकोन में, आर एंड डी में बिठाये रखते हैं और वे जानबूझकर ऐसे काम करवाते हैं ताकि पब्लिक सेक्टर बदनाम हो और उसका काम आगे न बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टिस्को क्या कर रहा है? टिस्को के स्टील की क्वालिटी सबसे अच्छी है और हमारी क्वालिटी, मतलब पब्लिक सेक्टर की क्वालिटी उसकी तुलना में कम है। इसलिये यह कंपनी ज्यादा मुनाफा कमा रही है और हमको धोखा देती है और यह हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। 10 प्रतिशत जो उसका स्टील है, ए ग्रेड का, उसको वह रिजेक्ट लिख देती है और उसको बेचती है बढ़िया में। लेकिन उसके दाम नहीं दिखाती। टिस्को में टाटा के केवल 3 फीसदी से भी कम 2.8 फीसदी शेयर हैं। लेकिन फिर भी हम उसको मैनेजमेंट दिये हुए हैं। वह शेयर होल्डर्स का मुनाफा मारता ही है और यह जो रिजेक्ट करता है 2 लाख टन उसके 20 प्रतिशत पर जो वह रिजेक्टेड "आर" लिख देता उसको वह नहीं दिखाता है। क्योंकि मैं टाटा में रहा हूं इसलिये मैं टाटा की एक एक बात को जानता हूं, उसकी नब्ज को जानता हूं, गली से, नली से सबसे परिचित हूं और उसकी सारी प्रक्रिया मैं जानता हूं कि वह किस तरह से चोरी होती है। तो दो सौ करोड़ रुपया तो केवल अच्छे स्टील पर रिजेक्टेड लिख देने से और बढ़िया स्टील के दाम में बेचने से फायदा उठा लेता है और हमारा टेक्स भी मारता है। इसी तरह से कोयले का सब जगह राष्ट्रीयकरण हो चुका है लेकिन टिस्को कारखाना चलाने के नाम पर उसको कोयले की खानें दे दी गई हैं। उसमें अच्छे कोयले को रिजेक्टेड लिख देता है। रिजेक्टेड लिखने से अच्छे कोयले की रायल्टी जो 6 रुपये है उसकी जगह बिहार सरकार को 8 आने की रायल्टी देता है और रिजेक्टेड माल सस्ता दिखाकर सब हड़प कर जाता है। मैं यह कह रहा हूं कि यह जो युद्ध है इन लोगों के बीच में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में इस्पात मंत्री उस युद्ध को खुल्लमखुल्ला आने में टाटा को सहारा देकर और प्राइवेट विदेशी मल्टीनेशनल्ज को सहारा देकर अपनी कम्पनियों को भूखा मार कर मल्टीनेशनल्ज के साथ टाटा का हाथ मिलाया है। यह मेरा चार्ज है और मैं समझता हूं कि इसमें बहुत भारी घपलेबाजी की गई है। 10 हजार करोड़ रुपये में, अब मैं असली बात बोल देता हूं (**व्यवधान**) नहीं तो हल्ला हो जाएगा। मुझे अभी बात कहनी है मैं कोई फालतू बात नहीं बोल रहा हूं। मैं जो बात बोल रहा हूं यह सब समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। कारखाने का माडर्नाइजेशन होगा तो एच० ई० सी० काहे के लिए बना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारा लक्ष्य यह है कि जब चार कारखाने बन जाएंगे उसके बाद हर साल कम से कम एक मिलियन टन का उत्पादन बढ़ जाएगा तब इस देश की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी और वहीं एक मिलियन टन प्रति साल बढ़ाने के लिए उन्होंने मेकोन और आर०एंड डी० एच० ई० सी० बी०एच०ई०एल० तमाम चीजों का हम माडर्नाइजेशन करेंगे तो इलक्ट्रीकल इक्विपमेंट की जरूरत भी पड़ेगी, कई तरह के मेकेनिकल इक्विपमेंट और सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको भूखा मार रहे हैं। एच०ई०सी० में मैं गया। वहां के चेयरमैन और दूसरे लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग भूखे मर रहे हैं। अगल-बगल के जो लोग जब कर सकते हैं हमारी पब्लिक सेक्टर की कम्पनियों का माल मिडलईस्ट में जाता है वहां हम स्टील बनाते हैं और यहां हम अपने घर में नहीं लेते हैं। जान-

[श्री राम अवधेश सिंह]

बूझकर पब्लिक सेक्टर को बदनाम करने की कोशिश इस्पात मंत्रालय के लोग*

उपसभापति : आप किसी का नाम नहीं लेंगे राम अवधेश जी। This will not go on record.

आप इस्पात मंत्रालय की माडर्नाइज़ेशन पर बोलिये उसके बाहर मत जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह : आपको मालूम है यह जो मेकोन है डिज़ाइन करने वाली कम्पनी है। उसके चेयरमैन और बी० कृष्णामूर्ति में आपस में कोई बातचीत नहीं है। दोनों में खुल्लमखुल्ला लड़ाई है और चाहते हैं कि हम उसको खा जाएं और बेचारे गरीब आदमी का कोई सहारा नहीं है। तो मिस्टर लाहा से इनकी कोई बातचीत नहीं है। यह सेल के चेयरमैन हैं इनको माडर्नाइज़ेशन करने की जिम्मेदारी है।

श्री माखन लाल फोतेदार : किनको लाहा से बातचीत नहीं है ?

श्री राम अवधेश सिंह : श्री वी० कृष्णामूर्ति को।

यह मैं कह रहा हूं क्योंकि ये लोग ऐसे टर्म्स में हैं। ये चाहते हैं उसको खत्म कर दें। उसको एक्सटेंशन न मिले। इनको एक्सटेंशन मिलता रहे। ये घी के दिए जलाते रहें।

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA (Delhi): Madam, if you would kindly go through the record and see if there is anything that is not quite right, then you could have it expunged.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will go through the record. That has already been expunged.

---

*Not recorded.

उपसभापति : राम अवधेश जी आप अपने मुद्दे पर बात करिये। साढ़े 8 बज गये हैं। आप बोलना बंद करिये।

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : दूसरे किसी को मौका नहीं देंगे। वे इसलिए बोलते हैं कि खत्म करके किसी दूसरे को मौका न मिले। अभी दो मिनट देखकर हम भी जाने वाले हैं।

उपसभापति : आप इस पर जल्दी बोलिए नहीं तो दूसरे सब लोग जा रहे हैं।

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : अब क्या करेंगे हम लोग तो चले जायेंगे। समय की कोई पाबंदी नहीं है तो हम लोग चले जायेंगे।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस बात की जांच कराये और सरकारी जांच नहीं, सर्वदलीय, पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय कमेटी जांच करे। इस बात की जांच करे कि क्या वजह है कि बिड़ला को जिसके पास स्टाक बहुत कम है . .

उपसभापति : आपने रिपीट कर लिया है।

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : उपसभापति जी, अब कभी समय मिलने पर इस विषय पर बोलेंगे, अभी आज इजाजत दीजिए . . . (व्यवधान) कुछ मुझे दूसरा काम है। दूसरी हमारी मीटिंग है। अभी 10 मिनट के अंदर मुझे जाना है और 10 मिनट के अंदर तो ये . . .

श्री राम अवधेश सिंह : मैं 10 मिनट में बोल दूंगा, खत्म कर दूंगा।

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : 10 मिनट के अंदर मुझे समाप्त करके जाना है।

श्री राम अवधेश सिंह : यह बहुत सीरियस मामला है।

उपसभापति : अब आप सवाल पूछ लीजिए और कृपया बैठ जाइये। आपने सब रिपीट कर लिया है, मुझे याद हो गया है।

श्री राम अवधेश सिंह : 461 करोड़ का ठिकला टेक्निकल सर्विसेज को क्यों दिया गया। उसके पास क्या संसाधन है स्टाक बहुत कम है फिर भी उनको लाभ कमाने के लिए यह दिया गया। महोदया, यह मेरा चार्ज है कि इस डील में इस्पात मंत्रीजी ने बहुत भारी घपलेबाजी की है और सारी मर्यादाओं को तोड़कर सारे नियम कानूनों को तोड़कर...

उपसभापति : आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री राम अवधेश सिंह : मैं चार्ज कर रहा हूं, वे जवाब दे दें। ही इज हियर... (व्यवधान)

उपसभापति : इस तरह आप चार्ज नहीं कर सकते।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं चार्ज लगा रहा हूं...

SHRI JAGESH DESAI: You cannot make allegations like this. Madam, he cannot say like this. (*Interruptions*).

श्री राम अवधेश सिंह : मैं एलीगेशन लगा सकता हूं। वे यहां है। ये उस चार्ज का जवाब दे दें...(व्यवधान) यह तो अच्छा है कि 5 ही आदमी हैं। पूरा हाउस होता तो बात ही नहीं चलने देते...(व्यवधान)

उपसभापति : आपको संभालने के लिए मैं अकेले काफी हूं। कोई फिक्र की बात नहीं है। देखिए, मैंने उस दिन भी आपको नियम सिखाये थे कि अगर किसी पर आप चार्ज लगाना चाहते हैं, किसी मेम्बर पर या मंत्री पर, तो आपको उसकी नोटिस चेयरमैन साहब को देनी पड़ेगी और उनकी अनुमति लिये बिना आप इस तरह का चार्ज नहीं लगा सकते हैं। कृपया आप माडर्नाइजेशन पर बोल चुके हैं इसलिए अब आप बैठ जाइये मैं दूसरे मैम्बर को बुलाऊंगी।

श्री राम अवधेश सिंह : यह कैसे हो सकता है।

उप सभापति : यह हो सकता है... (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : महोदया, मैं कह रहा हूं कि आप मनमानी मत करिये।

उप सभापति : मैं मनमानी नहीं कर रही हूं... (व्यवधान)

आपको काफी समय दे दिया है अब एक मिनट मैं बात खत्म करके बैठ जाइये मैं घंटी बजा रही हूं... (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि लिखित तौर पर हमने दिया है।

उप सभापति : नहीं आपने नहीं दिया है। चेयरमैन साहब ने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री राम अवधेश सिंह : मैंने लिखित चिट्ठी दी है, चेयरमैन साहब को दी है।

उपसभापति : आपको परमिशन नहीं दी है।

श्री राम अवधेश सिंह : और उसी के आधार पर कालिंग अटेंशन के लिए राजी हुए, तभी कालिंग अटेंशन का प्रोफार्मा हमने दिया। इसलिए पूरी सूचना है और मैं पूरी तौर पर इनको चार्ज कर सकता हूं और ये सदन में जवाब देने में सक्षम हैं।...और यह सदन में जवाब देने में सक्षम हैं।... (व्यवधान)

उपसभापति : नहीं, आप बैठ जाइये। राम अवधेश सिंह जी आप मेरी बात सुनिय। कालिंग अटेंशन जब आता है, तो वह किसी विषय के ऊपर आता है। आपने यह कहा कि माडर्नाइजेशन के ऊपर ज्यादा खर्चा हुआ है।

[उपसभापति]

इसलिए चेयरमैन साहब ने आपको अनुमति दी, मगर आपको किसी मंत्री या मेम्बर के ऊपर चार्ज लगाने की अनुमति, चेयरमैन साहब ने नहीं दी है और मैं भी नहीं दूंगी।

श्री राम अवधेश सिंह : यह बात आप नहीं कह सकती हैं।

उपसभापति : मैं कह सकती हूं।

श्री राम अवधेश सिंह : आप कैसे कह सकती हैं?

उपसभापति : आप बैठ जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं नहीं बैठूंगा।

उपसभापति : आप ज्यादा बोलेंगे, तो ... (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : यह बात नहीं चलेगी। इस बात पर जब प्रापर नोटिस के जरिए आज यहां डिसकशन हो रहा है, तब हम इनसे सारी बात पूछ सकते हैं। यह यहां पर जवाब देने के लिए तैयार हैं।

यह जवाब दें कि देशी कम्पनियों को अन्डरमाईन करके विदेशी मल्टी-नेशनल के साथ जो समझौता किया गया है उसके पीछे क्या साजिश है और उसी आधार पर जब एक हजार करोड़ में देशी कम्पनी एक मिलियन टन बढ़ा सकती है तो यह अढ़ाई करोड़ लगा कर .7 या .8 मिलियन टन यह कैसे बढ़ाते हैं?

इसलिए मेरा चार्ज है कि विदेशी कम्पनियों से भारी मात्रा में इन्होंने*

उपसभापति : यह बिल्कुल गलत है।

श्री राम अवधेश सिंह : *

*Not recorded.

उपसभापति : आप इसको नोट नहीं करेंगे।... (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : नोट कैसे नहीं होगा। यह सदन मनमानी से नहीं चलेगा। इसकी मैंने सूचना दी है कि यह जवाब दें कि क्या कारण है कि एक हजार करोड़ रुपये से देशी कम्पनी माडर्नाईज करती है और उतने से कम के लिए अढ़ाई हजार स... (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप बैठ जाइये। वह आपको जवाब देंगे।

श्री राम अवधेश सिंह : आप कहते हैं कि डिलीट हो जाएगा ... (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप चार्ज नहीं लगायेंगे

श्री राम अवधेश सिंह : मैं चार्ज लगाऊंगा क्योंकि मैं चार्ज लगाने के लिए ही यहां हूं। यह जवाब दें। आप क्या बात करते हैं? आप लोग इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि आप ने डिलीट करने के लिए कैसे कहा है?

उपसभापति : आप सवाल करिए और उसके बाद बैठ जाइये। वह आपको जवाब देंगे।

श्री राम अवधेश सिंह : आप ऐसा मत करिए। हम लोगों को ऐसे मत दबोचिये। आप हम लोगों के अधिकार की रक्षिका हैं उस कुर्सी पर। आप हम लोगों का गला दबाना चाहती हैं। जनतंत्र में प्रतिपक्ष की तीखी से तीखी बात भी सुननी चाहिए।

श्री राधाकिशन मालवीय (मध्य प्रदेश) महोदया, मेरा प्वांइट आफ आर्डर है माननीय सदस्य ने जो कालिंग अटेंशन दिया है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि स्टील प्लांट का माडनाइजेशन करने के संबन्ध में पर यह बिना वजह मंत्री को इनवाल्व कर रहे हैं ... (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : आप पढ़िये लिखा हुआ है। यही तो मेरा कहना

कि इतन कास्ट इनवाल्वड है, यही मैंने लिखा है ।

उपसभापति : राम अवधेश सिंह जी आप अभी इस कुर्सी पर नहीं बैठे हैं कि उनको जवाब दें । उन्होंने मुझसे जवाब मांगा है मुझे उनको रूलिंग देनी है, आप बैठ जाइये ।

श्री राधाकिशन मालवीय : आपने पहले प्रधान मंत्री का नाम लिया... (**व्यवधान**) तो वह उनके अधिकारी और उनको एक्सटेंशन दिया... (**व्यवधान**)

दूसरी बात, अब यहां पर माननीय मंत्री पर बिना वजह चाहे जो आरोप लगा रहे हैं, जबकि ... (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : मैंने तो उदाहरण दिया । इसमें टिस्को इनवाल्वड है जोकि एक हजार करोड़ रुपये में आपको एक मिलियन टन का उत्पादन करता है और अढ़ाई हजार करोड़ में केवल .7 या .8 मिलियन टन करेंगे, यह क्या बात है ?

श्री राधाकिशन मालवीय : आपको प्रूफ के साथ बोलना चाहिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : माडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है ? माडर्नाइजेशन का मतलब होता है उत्पादकता बढ़ाने के लिए । उत्पादकता यदि आपकी नहीं बढ़ती है, उस तरह से खर्च करते हैं तो उसको क्या कहिएगा, बोलिये ?

श्री राधाकिशन मालवीय : अभी मंत्री जी आपको जवाब देंगे ।

श्री राम अवधेश सिंह : माडर्नाइजेशन आधुनिकता का मुख्य लक्ष्य होता है उत्पादन बढ़ाना और उत्पादकता आप उस रेशो में नहीं बढ़ा रहे हैं, जिस रेशो में स्वदेशी कम्पनी बढ़ाती है । तो इसके एवज में हम क्या कहें, आप बताइये ? आप हमारी जगह में होते, तो क्या बोलेंगे ? आप प्रतिपक्ष में रहते और मैं मंत्री रहता उनकी जगह पर, तो आप क्या बोलते ?

एक माननीय सदस्य : आप कभी मंत्री होने वाले नहीं हैं ।

श्री राम अवधेश सिंह : नहीं, बहस के लिए मान लीजिए । यह कभी हो भी सकता है । ऐसा मत समझो कि हमारी जगह उधर नहीं जाएगी और आपकी जगह इधर नहीं आएगी और वह समय दूर नहीं है । लेकिन मैं यह कह रहा हूं ... (**व्यवधान**) देखिये, आप हल्ला मत करिए, मैं सीधे क्वेश्चन पूछ रहा हूं... कि एक हजार करोड़ में टिस्को माडर्नाइज करके एक मिलियन टन बढ़ाता है और आप 2668 करोड़ रुपया खर्च करके .7 या .8 ... (**व्यवधान**) ... और माडर्नाइजेशन का उद्देश्य बताते हैं कि हम उत्पादकता बढ़ायेंगे । क्या उत्पादकता आपकी बढ़ी है ? इसलिए मेरा चार्ज है कि भारी मात्रा में चुनाव के लिए चंदा लिया गया है और इस्पात मंत्री ने* इसकी जांच कराई जाए ? ... (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप मत बोलिए । ... (**व्यवधान**) आप बैठ जाइये । राम अवधेश जी आपका समय खत्म हो गया, अब आप बैठ जाइये ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं जांच की मांग करता हूं । इसकी संसदीय समिति जांच करे । अगर संसदीय समिति जांच करती है . (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप चार्ज लगायेंगे तो नोट नहीं होगा ।

श्री राम अवधेश सिंह : अगर संसदीय समिति की जांच की बात मान लेते हैं तब तो हम मानेंगे । ... (**व्यवधान**)

उपसभापति : जो इन्होंने बगैर परमिशन के चार्ज लगाया वह रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

SHRI JAGESH DESAI: Madam, it should not go on record.

उपसभापति : जो इन्होंने बगैर परमिशन के चार्ज लगाया वह रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

---

*Not recorded.

श्री राम अवधेश सिंह : महोदया, यह कोई बात नहीं है।... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर ठाकुर (बिहार) : यह उचित नहीं है, यह नियम विरुद्ध है।

श्री राम अवधेश सिंह : ऐसा आप कैसे करेंगे।

उपसभापति : राम अवधेश जी, मैंने आपको कहा कि आपने जिस विषय पर कालिंग अटेंशन दिया है उसमें आप सवाल करके बैठ जाइये। आप काफी समय ले चुके हैं। मैंने आपको 15 मिनट दिए थे और आप 36 मिनट बोल चुके हैं, इसलिए आप सिर्फ मंत्रीजी से सवाल करिए और वह उसका जवाब देंगे। मगर आप किसी के ऊपर चार्ज नहीं लगा सकते करप्शन का बिना परमिशन के, इसलिए आप बैठ जाइये और वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री राम अवधेश सिंह : यह तो आप पहली बार ऐसी बात बोल रही हैं। हम लोग भी पहली बार सदन में सुन रहे हैं। हमारा भी 20 साल का संसदीय जीवन है, लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि आप मंत्री पर चार्ज नहीं लगा सकते। ऐसा तो हमने कहीं सुना ही नहीं। मंत्री जी को लिखित सूचना दी है और इसके बावजूद भी आप कहती हैं आप चार्ज नहीं लगा सकते हैं।... (व्यवधान) सवाल का जवाब दिलाइये ... (व्यवधान)।

उप सभापति : आपने मंत्री जी को सूचना दी है माडर्नाईजेशन के बारे में मालूमात करने की आपने अपने कालिंग अटेंशन में यह कहीं मेंशन नहीं किया है, इसलिए वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री राम अवधेश सिंह : उसमें कास्ट इन्वाल्व है और कास्ट क्यों इन्वाल्व है?

उपसभापति : हां, कास्ट इन्वाल्व जितनी भी है उसका भी जवाब देंगे कि क्यों इन्वाल्व है। मगर इसका मतलब न है... (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : क्यों ...

उप सभापति : नहीं, राम अवधेश जी आप बैठ जाइये। ... (व्यवधान) एक मिनट जब मैं क्लेरिफिकेशन दे रही ... (व्यवधान)) आपने कास्ट इन्वाल्वमेंट का सवाल किया है वह उसका जवाब देंगे कि कास्ट क्यों इन्वाल्व है। मगर आप इस तरह से किसी पर चार्ज नहीं लगा सकते हैं।

मैं आपको इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदया, एक बात सुन लीजिए, एच०ई०सी० ने जब.. (व्यवधान)

उपसभापति: बस, अब आप बैठ जाइ

श्री राम अवधेश सिंह : एच०ई०सी० ने टेंडर में जब कंपीट किया और उसको छांट करके दूसरी कंपनियों को दिया गया, आखिर इसका क्या कारण है, एच०ई०सी० पब्लिक सैक्टर है, कोई प्राइवेट नहीं है, तो इसके बारे में य बताएं और मैं यह चाह रहा हूं (व्यवधान)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : कोई सम निर्धारित है या नहीं ?

उप सभापति : अब आप बैठ जाइये

श्री राम अवधेश सिंह : मैं यह चाह रहा हूं कि यह कमीशन मोटे तौर पर...

उप सभापति : अब आप बैठ जाइये आपका समय समाप्त हो गया। आपका समय पूरा हो गया। अब आप बैठ जाइये

श्री राम अवधेश सिंह : अगर मंत्री जी, हमारे चार्ज से, हमारे अभियोग से सहमत नहीं हैं और मैं समझता हूं कि सहमत नहीं होंगे क्योंकि कोई मंत्री अपने ऊपर चार्ज सहज रूप से नहीं लेता है और यह नहीं सहमत होंगे, तो मैं चाहता हूं कि एक संसदीय समिति बहाल कर दी जाए मेरी बातों की और वह

जो अभी जवाब देंगे यह दोनों की जांच करे घूमकर, अगर यह बात गलत हो तो तब यह आगे जो कहेंगे मैं सुनने के लिए और सहने के लिए तयार हूं, कोई दंड भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले सारी चीजों की जांच हो जाए और वी० कृष्णा मूर्ति की सारी कारवाइयों और नीचे से ले करके ऊपर तक की तमाम कार्रवाइयों की जांच हो जाए कि कहां-कहां क्या किया ? तब वह पूरा पुलिंदा खुल जाएगा, खाली जांच बैठा दीजिए तो इनका सारा करिश्मा खुल जाएगा कि ये कितने करिश्माबाज हैं ?

उपसभापति : पहले आप बैठ जाइये । श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी ।

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Madam Deputy Chairman, I do not want to make the discussion lengthy. I only want to say a few words and then put two or three questions. Most of the things he has said. I do not want to go into all those things. I had noted down many points but there is no time to go into them because I have to go, to attend another meeting. First of all, I would like to request the Minister. Of course, Shri Ram Awadhesh Singh has made certain allegations while speaking on this Calling Attention motion. If the Minister wants to clear these doubts, let him explain to the House whether there is any truth in these allegations or not. He has got those doubts in his mind. So, he is expressing those doubts. So, it is fair on the part of the Minister to clear those doubts.

Another important thing is, in order to modernise the steel plants, the Steel Authority of India and the Steel Ministry might have taken steps, might have discussed what measures have to be taken which are the companies to which this work has to be entrusted. I would like to know from the Minister whether this technical knowledge is available in the country, whether foreign countries, foreign companies are to be approached, whether it is necessary, whether the Steel Ministry and the Steel Authority of India have discussed and come to a conclusion. That has to be cleared.

There is also a doubt that the Indian companies have been ignored and that foreign companies have been entrusted with the modernisation work, as a result of which there is large-scale unemployment. And public companies, especially all the public sector construction and manufacturing companies are starving, and they are facing unemployment problem. And the Steel Ministry and the SAIL are allotting the modernisation jobs to a multinational companies consortium, which is a broad day-light robbery of the nation's wealth. This allegation is there. I would like to know whether Indian public construction companies have been ignored, whether there is such a large scale loot of the nation's wealth. If it is so, if there is any truth, the Government must take all necessary steps to see that Indian money should not be looted. No country, no party, no government will allow such things to happen. So, I would like the Minister to clarify and satisfy this House and the country as a whole.

Secondly, I would like to know from the Minister whether the Steel Ministry has created many public sector companies in order to improve them, modernise them and all these things. I think these things have been organised by the Steel Ministry and the SAIL.

The Research and Development Centre for Iron and Steel was set up in 1973 to provide the latest technology

[Shri B. Satyanarayan Reddy]

to the steel Industry so that in future the Indian steel Industry should not be in need to seek technical knowledge from outside.

Secondly, the Metallurgical Engineering Consultants, that is, MECON, is controlled by the Steel Ministry.

The SAIL has the latest equipment and the latest design with enough staff which is able to design two steel plants at a time.

The third one is the CET, Centre for Engineering Technology.

Information about these things I have got. The Steel Ministry, the Steel Authority of India created these organisations. The work was entrusted. But later on it seems that the work that had been entrusted to some of these organisations, has been rejected and refused. I do not know the details. But, I would like the Minister to clear these doubts.

Originally, the MECON had given a design for the modernisation of the Durgapur Steel Plant, which should have cost Rs. 900 crores in 1984. Later on, with some more additions, and modernisation, it increased to Rs. 1,300 crores. But the MECON design was bypassed and rejected by the Steel Ministry and the Steel Authority of India, and the design and the construction for the modernisation work was allotted to a German company which has formed a multinational consortium. Now, it would cost Rs. 2,668 crores. These are some of the things which are there on the record. So, it is but proper on that part of the Minister to clairfy these things. When under an Indian company there can be a lesser cost, why should we entrust these things to a foreign multi-national company? Mr. Ram Awadhesh Singh has already spoken on the cost question that by taking this work of modernisation there is an escalation of cost and loot of money. The allegation is that the money has been looted by the multinational companies. So, let the Minister clarify these things and say how he is going to modernise and increase production in the steel industry without putting the nation into trouble. The Miniser in his statement has said that our plants have become useless and production has become less. There is need to modernise the plants. We welcome all steps should be taken to modernise the steel plants. Unless they are modernised and the steel production is increased, enough steel will not be there for the country's progress. But at the same time the Steel Authority and the Ministry must take all necessary steps to ensure that there is no loot. I request the Minister to clarify all the doubts which Mr. Ram Awadhesh Singh has expressed during the discussion.

Moreover, there should not be any unemployment and the workers who are unemployed in different steel plants should be absorbed. The workers working in the public sector construction and manufacturing companies should not be deprived of employment in the name of modernisation by entrusting the work to the multi-national companies. So far as our employees and workers are concerned, they should not be put to any trouble and should not be retrenched. Moreover, these companies which are in existence should have full work. I would give one instance and then I will finish. The public sector construction company had to approach the Birla companies to get their work because they are not having work. Such a situation should not be created in the country. It is most regrettable and deplorable. So, all steps should be taken to see that public sector construction companies are not put into trouble and there is no unemployment and loot by entrusting it to the multi-nationl companies.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is the name of Mr. Mostafa Bin Quasem, CPM, and also of Mr. Mohammad

Amin. Are you going to speak from the CPI?

श्री मोहम्मद अमीन : (पश्चिमी बंगाल) : यस मैडम, टाइम कितना है, बता दीजिये ?

उपसभापति : आप सवाल कर लीजिये क्योंकि कालिंग अटेंशन में जो पहले स्पीच देते हैं, उन्हें 15 मिनिट रहते हैं। आप अपने सवाल पूछ लीजिये क्योंकि वे काफी बोल चुके हैं।

श्री मोहम्मद अमीन : फिर भी पांच मिनिट, दस मिनिट ?

उपसभापति : आप पांच मिनिट बोल लीजिये।

श्री मोहम्मद अमीन : मोहतरमा, कालिंग अटेंशन के जवाब में मंत्री जी ने जो बयान दिया है..मोहतरमा, कालिंग अटेंशन के जवाब में जो बयान मंत्री जी ने दिया है, उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उससे फौलाद की सनद में इस वक्त जो हालत है उसकी ठीक अक्कासी नहीं हो रही है और मैं दो मिसालें इस सिलसिले में देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह जो साल मंसूबे बने हैं, इसमें हुकूमत का रवैया क्या रहा है ? स्टील सैक्टर में जो एलोकेशन हुआ पहले प्लान में 0.88 परसेंट, दूसरे प्लान में 4.50 परसेंट, तीसरे प्लान में 5.29 परसेंट, चौथे प्लान में 4.23 परसेंट, उसके बाद फिर घटना शुरू हो गया, पांचवें प्लान में 3.30 परसेंट, छठे प्लान में 2.32 परसेंट और सातवें में 1.80 परसेंट। तो यह है हुकूमत का हिसाब और इससे यह बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि स्टील के प्रोडक्शन में हिन्दुस्तान एक जमूद की कैफियत से गुजर रहा है, स्टेगनेशन की कैफियत से गुजर रहा है।

दूसरी मिसाल क्या है कि इस वक्त मुल्क में फौलाद की पैदावार हो रही है सालाना 13 मिलियन टन जिसमें लगभग 7 मिलियन टन पब्लिक सेक्टर में है और 6 मिलियन टन है प्राइवेट सेक्टर में। यानि प्राइवेट सैक्टर करीब-करीब पब्लिक सक्टर की बराबरी कर रहा है और अगर पर-कैपिटा के हिसाब से देखें तो वह 17 किलोग्राम पड़ता है और इसी के साथ आप यह देखें कि 1947 में हिन्दुस्तान में फौलाद का जो पैदावार होता था, उससे भी कम पैदावार होती थी चीन में, लेकिन इतने दिनों में हिन्दुस्तान 13 मिलियन टन के ऊपर पहुंचा है और चीन की पैदावार पहुंच गई है 56 मिलियन टन पर। यानि चार गुणा से भी ज्यादा और पर-कैपिटा उनका कंजम्पशन है 70 किलोग्राम। पर-कैपिटा के हिसाब से भी चार गुणा से ज्यादा उनकी पैदावार बढ़ गई है। तो चीन और हिन्दुस्तान की मआशी हालत में तो बहुत यक्सानियत, यक्सानियत नहीं बल्कि हिन्दुस्तान से ज्यादा खराब हालत चीन की थी, वह कहां चले गये और हम लोग कहां चले आए हैं।.. (**व्यवधान**)

श्री माखन लाल फोतेदार : देखकर आया हूं वहां से।...(**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अमीन : देखकर आये हैं तो यह फिगर हमने आपके सामने रखा है, अब आप उसका जवाब दे सकते हैं कि चीन में काहे 56 मिलियन टन हो रहा है और हम 13 मिलियन टन पर पड़े हैं। अगर हमसे पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इकानोमी अभी दो तरह की हैं—एक है कपेटलिस्ट इकोनोमी और दूसरी है सोशलिस्ट इकोनोमी। उनके यहां सोशलिस्ट इकोनोमी है। आपके यहां न केपेटलिस्ट इकोनोमी है और न सोशलिस्ट इकोनोमी है, आप दोनों के बीच में हैं, मिक्स्ड इकोनोमी है और मिक्स्ड इकोनोमी का जो अंजाम होना चाहिये, वह हो रहा है। इसलिये माडर्नाइजेशन की जो जरूरत है, वह बहुत अहम है। इसमें कोई शक नहीं है कि माडर्नाइजेशन किये बगैर इस हालात से आप निकाल सकते हैं... (**व्यवधान**)

श्री माखन लाल फोतेदार : आप चीन होकर आइये और मुझे बताइये। (**व्यवधान**).

श्री राधाकिशन मालवीय : आप चीन जाइये, प्लान को देखिये और उसके बाद बताइये । . . . (**व्यवधान**)

SHRI MOSTAFA BIN QUASEM (West Bengal): He is saying that. Is he cutting jokes?

श्री मोहम्मद अमीन : जी हां । चीन मैं भी गया था । चीन आप ही नहीं गये, मैं भी गया था ।

I was there for 21 days and I have studied.

SHRI MOSTAFA BIN QUASEM: You have got no right to undermine a Member in this House itself by putting questions like that.

श्री मोहम्मद अमीन : यह तो कोई तरीका नहीं हुआ । अब देखिये, "इसको" कारखाना, वह नेशनलाइज्ड हुआ, अब उसकी हालत यह है कि वह जापानियों के हवाले किया जा रहा है । क्या तरक्की करेंगे; कैसे करेंगे आप ? सभी स्टील प्लांट तीन मिलियन टन पैदावार कर रहे हैं, ये सब प्राइवेट सेक्टर में है और लाइसेंस आपने जारी किया है 22 मिलियन टन का । क्या जवाब है आपके पास ? क्या आऊट लुक है ? क्या चाहते हैं आप ? सैल्फ रिलायंस की इकोनोमी इसी से तैयार होगी ? . . . . (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : जवाहर लाल जी को चबा देना चाहते हैं लोग । . . . (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अमीन : तो इसलिये यह एक क्योटिक पालिसी पर गवर्नमेंट आफ इंडिया चल रही है इस पालिसी को बदलने की जरूरत है । इसमें जोर जबरदस्ती और हुज्जत से काम नहीं चलेगा ।

माडर्नाइजेशन के बारे में जो आपकी स्कीम है वह यह है कि अगले 12 वर्ष में 15 हजार करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा । स्टील अथारिटी आफ इंडिया का जो बुलेटिन निकलता है उसको मैं पढ़ता हूं । उससे मैंने आंकड़े कलेक्ट किये हैं । ठीक है कि हजार करोड़ रुपया खर्च हो, लेकिन इस बात के ऊपर दिया जा रहा है कि पावर कम की जाये, मजदूरों की त घट जाये, मजदूरों की तादाद घटाकर का एक और मसला जो बेकारी का है और बढ़ेगा । अगर आप मजदूरों, कि और मुल्क के लोगों की मुफाद की देखकर मंसूबा बनायें तो एक बात है, ले यह सलाह आपको वर्ल्ड बैंक और नेशनल्स दे रहे हैं, तो उनकी सलाह म पर आप क्यों मजबूर हैं यह बात जा हम तो यह कहेंगे कि उनकी सलाह म मुनासिब नहीं है इसलिये कि वे हिन्दुस्त के दोस्त नहीं हैं । पूरी सरमायेदार दु बोहरीन में फंसी है । वह अपनी कमा तीसरी दुनिया के मालिकों को मुस्त करना चाहते है और आप कहते हैं यह आ रास्ता है । इसलिये फौलाद की सनत बैंक की मनहूस छाया पड़ी तो हिन्दुस्त की सनतबन्दी को नुकसान पहुंचेगा, इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं ।

आपने जो प्लान बनाया है उसमें 2 सदी के खात्मे तक आपकी जरूरत मिलियन टन होगी । माडर्नाइजेशन जो 15 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा, आपका निशाना ठीक ठीक पूरा हो गया आप 20 मिलियन टन बना सकेंगे 5 मिलियन टन आपको बाहर से मंग पड़ेगा । यह क्या मंसूबा हुआ ? मैंने लिये चीन की मिसाल आपको दी । जापान, अमरीका के बाद चीन चौथी ता हो गई है । फौलाद की पैदावार में आप पड़े हुये हैं वह लिस्ट में अपना नाम निकाल देख लीजिये, आपको मालूम हो जायेग इसलिये भी ज्यादा अफसोस हमें होता है हिन्दुस्तान में फौलाद की पैदावार के जिन चीजों की जरूरत है, जैसे आयर और, मैंगनीज, डोलोमाइट और कोयल ये तमाम चीजें हिन्दुस्तान में काफी मिकद में हैं, काफी अच्छी क्वालिटी में हैं, उन ठीक से काम में लाया जाय तो हिन्दुस्त फौलाद की पैदावार में बहुत तेजी से बढ़ सकता है । लेकिन वह तो हो नहीं र है । आखिर इसकी वजह क्या है ? अगर बात आप नहीं बतायेंगे तो बात साफ न

होगी। इसलिये मेरे ख्याल में तमाम कारखानों के जो अलग अलग तफसीलात हैं मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वक्त नहीं है; आपने जो वक्त दिया है उसके अन्दर मैं उसूल की बातें कहने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि अगर हुकूमत अपनी इस पालिसी को बदलकर इस बात को ध्यान में रखकर कि हम मजदूरों की भलाई, देश की भलाई के ध्यान से अपने मंसूबे बनायें, अगर अपनी पालिसी को तरतीब दें तो उनकी कामयाबी हो सकती है। मिसाल के तौर पर पब्लिक सैक्टर में जो फौलाद के कारखाने हैं उनमें 75 हजार मजदूर कांट्रेक्ट लेबर पर हैं। आपके पास इसका क्या जवाब है ? 30-40 वर्ष के बाद भी कांट्रेक्ट लेबर आप खत्म नहीं कर सके; उसका एक्सप्लायटेशन होता है, जिस तरह से वे लूटे जाते हैं, यह बात आप जानते हैं। लेकिन आप तमाशा देख रहे हैं। इसलिये इस सनत को बचाने के साथ साथ मजदूरों को भी बचाना होगा। आप माडर्नाइजेशन के सिलसिले में ऐंसिलियरी जाब जो होते हैं उनमें मुकम्मिल सनत स्माल स्केल इंडस्ट्री को मिले, इसकी तरफ ध्यान दें। इस के बारे में दुर्गापुर के सिलसिले में जो फैसला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, मेरे ख्याल में वह बिलकुल ठीक हुआ है। मेरे ख्याल में यह बिलकुल ठीक हुआ है कि ऐंसिलियरी का कम से कम 25 फीसदी काम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि ऐसा करने से काफी कुछ लोगों को मुलाजिमयत मिलेगी, रोजी मिलेगी अगर यह पालिसी पूरे देश में आप अपना लेते हैं तो भला हो सकता है। इतना ही मुझे कहना है

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam Deputy Chairperson, first of all, I would like to keep the record very straight. There were some remarks made against Shri Krishnamurthy, the Chairman of SAIL. I was a member of the Public Undertaikngs Committee and I had often had the advantage of hearing the views and seeing the work of Mr. Krishnamurthy. He was so confident that we would be able to achieve the target-production in due course and he also told me his plan for that purpose. Madam, as yau are well aware, the steel industries in public sector were running on loss. Now those losses have been wiped out, the past losses have been wiped out.

श्री राम अवधेश सिंह: स्टील की कीमत कितनी बढ़ी है यह तो बता दीजिए। जिन्होंने देश की जनता को लूट लिया, जो बेईमान हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

SHRI JAGESH DESAI: You please sit down. I will explain to you. Listen to me. (*Interruptions*) You will not understand anything. Please listen to me. (*Interruptions*) I have studied nthe subject very well, in detail. I am prepared to discuss it with you outside, not here. I know it.

श्री राम अवधेश सिंह: एक हजार करोड़ रुपये आपने बढ़ा दिये (**व्यवधान**)

SHRI JAGESH DESAI: Please listen to me. You do not understand and you want to interrupt. I know the subject very well. (*Interruption*) I do not have much time to speak. If the Steel Ministry is being discussed, I can bring all the facts before this House. But one thing I must tell you now. In just the last nine months, the production of steel has gone up by 10 per cent and that is because of the various measures of productivity taken by the Chairman. This time the profit has gone up to more than Rs. 300 crores. The losses are wiped out. I do not want to talk about that. But because he has mentioned the name of Mr. Krishnamurthy, I must... (*Interruption*).

श्री राम अवधेश सिंह: हम खूब समझते हैं, सब की चोरी समझते हैं। (**व्यवधान**)

SHRI JAGESH DESAI: I will speak whatever I want. (*Interruption*) I know. You sit down.

श्री राम अवधेश सिंह: यह बताइये कीमत बढ़ाने से कितना रुपया आया।

SHRI RAM AWADHESH SINGH: He is misleading the House

आप जो डिफेंड कर रहे हैं यह बताइये कितना रुपया...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He cannot answer. The Minister will answer.

जब आप बोले आपको किसी ने डिसटर्ब नहीं किया। जो आपने क्वेरी की उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप बैठ जाइये।

SHRI JAGESH DESAI: That is not my job. That is the job of the Minister. Madam, the Public Undertakings Committee had given a recommendation as regards the extension of the tenure of the Chief Executive. Those officers are doing excellent work. They should not be disturbed for five years, but they should be given extension. Here is a case of such good officers. I am proud of such officers. If we have such officers, then the public sector will reach the heights that we want it to.

श्री राम अवधेश सिंह: इसीलिए इतने दिन तक घाटे में चल रहा था।

श्री जगेश देसाई: आपको पता नहीं आप बैठ जाइये। आपको किसी ने दे दिया और आप बोल देते हैं। मैं आपकी बाबत कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन जिस ढंग से पब्लिक सेक्टर को बदनाम करना चाहते हैं मैं आपको कहने नहीं दूंगा। मैं पब्लिक सेक्टर का चाहने वाला हूं। पब्लिक सेक्टर अच्छी तरह काम करे इसी के लिए मैं हमेशा लड़ता रहा हूं। यह अच्छा काम कर रहे हैं उनको बधाई देना मेरा कर्तव्य है। मैं फोतेदार जी आप को भी बधाई देना चाहता हूं। यह जो 10 हजार करोड़ रुपये का माडर्नाइजड प्लांट है आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। यह आपके एफर्ट से और चेयरमैन साहब के एफर्ट से हुआ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने हमेशा पब्लिक सेक्टर की मदद की 10 हजार करोड़ का प्लांट सेक्शन किया है इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं दूसरे एक और अच्छा काम किया है। दूसरा अच्छा काम सेलम स्टील प्लांट में हुआ है

I was the convener of the group the PUC and they put before that only one mill was sanctioned and the second mill would be commissioned if they extended the plant, and they said that they were very happy that after our visit the second mill was going to be operated. So, this is what we are doing in the public sector and to say that we are helping the private sector is wrong and is not correct at all. Why should we invest thousands of crores of rupees in the public sector if we wanted to have the private sector? But there is one thing. For many years the steel industry was incurring losses and it was not properly maintained and it required modern technology to bring down the cost. The cost of production is higher in India, much higher than the cost in other countries. That is why many public sector units themselves want to import steel because by that process they can bring down their own costs. But I am sure that after this modernisation, the cost of production will come down and we would be able to compete even in the foreign markets. We want such projects to be established. But, at the same time, I would like to pose some questions to the Minister. I am sure that with the adoption of this policy by the Government that wherever equipment is available within the country with other public sector units, they should take it. I am sure this will help in bringing down the cost. As regards the import content, it is said that it is likely to be in the region of 20 per cent to 35 per cent of the total cost and it will be for five years or so. But most probably the technology in this country after five years will be such

that it may not be required. So, I would like to know from the honourable Minister whether in future this also will come down from the expected 20-35 per cent so that foreign exchange can be saved and how much foreign exchange you are going to save or you are going to spend less. If this is not done, then we will have to pay about five thousand crores or so while today we are paying only Rs. 1,500 crores. But by spending this much money now, you are going to save much foreign exchange and that is why I commend this technology. I am thankful to Shri Ram Awadhesh Singh for raising this matter and to the honourable Minister for this statement. I also hope that the Minister will assure us that whatever equipment is available with the other indigenious public sector units will be taken for modernisation. The Minister has already said in the state ment—and I would quote only one para—like this:

> "The thrust in this modernisation programme is to employ indigenously available skills and expertise to the fullest and also to procure whatever equipment can be manufactured within the country making the time schedule. Import content is confined to design and supply in respect of state-of-the-art technology and equipment which are not yet available in India. The import content is likely to be to the region of 20—35 per cent of the total cost of the programmes in each of the steel plants."

I am quite sure that within five years these steel plants will work well and the dream of Pandit Jawaharlal Nehru of the public sector achieveing the commanding heights of the economy will be realised by this kind of action.

With **these words, I support** the action of the Government.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Madam, I want to have just one moment if you permit me.

Madam, Members from both sides of the House have not questioned the very basic point about modernisation and I think that is what the calling-attention was about. From both sides, all the Members are for modernisation. But the question was only about the cost and it was whether we have gone speedily enough and whether the costs involved in this modernisation have been less as they should have been. This was the question. All I want to say, Madam, is that we must not lose sight of the 21st century. We are approaching the 21st century. As Mr. Ram Awadhesh himself said, the measure for any...

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): Madam, I am happy...

श्री राम अवधेश सिंह : हम तो आपसे कहते हैं कि आप लुटवाइये मत।

श्री विश्व बन्धु गुप्ता : जरा मेरी बात तो सुनिये। ... (**व्यवधान**) ... मैं आप की ही बात कह रहा हूं और आप उसको भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर आगे कैसे बात करें?

श्री राम अवधेश सिंह : लुटवाइये मत।

श्री विश्व बंधु गुप्ता : जो बात कह रहे हैं वही बात मैं कर रहा हूं। अगर आप सुनेंगे और ऊपर ही देखेंगे तो उससे कोई हल नहीं निकलेगा।

मेरी प्रार्थना यह है कि मैडम अगर हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और उसके लिये वे स्वयं कह रहे हैं, सब मानते हैं इस बात को कि स्टील प्रोडक्शन उसका नापतौल होगा, इस बात को देखने के लिये कि देश कितना आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है उस डाइरेक्शन में। इसलिये इसको बढ़ाने की और इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। इसलिये जो प्रोग्राम स्टील मिनिस्ट्री ने बनाये

[श्री विश्व बंधु गुप्ता]

हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिशों और उनकी दूरदर्शिता से बने हैं तो उस कोशिश को तेजी से आगे बढ़ाया जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें हमको बहुत सफलता मिल सकती है। मुझे आशा है कि हमारे मंत्री जी तथा हमारी सरकार इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। दूसरे देशों, और विशेषकर चीन का जिक्र यहां पर किया गया। चीन में मैं भी जा चुका हूं। मैंने सारे उनके प्रोग्राम देखें हैं। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उसमें तेजी लाने की जरूरत है, उसमें बाधायें डालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे एक मिनट बोलने का अवसर दिया।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: Madam, I am very happy, rather delighted to....

श्री राम अवधेश सिंह : हिन्दी में बोलिये। मैं समझ नहीं पाऊंगा तो क्या फायदा।

उपसभापति : आप लगा लीजिये जिसमें ट्रांसलेशन होता है।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: ... to have this motion before this House on the modernisation of integrated steel plants in the public sector.

Mr. Ram Awadhesh Singh has rightly said that the motion has been moved at a time which is the fag end of the day, of the session also. I would have liked such motion to come on the first day itself or in between. I will try...

श्री राम अवधेश सिंह : अगले सेशन में तैयार रहिये।

श्री विश्व बन्धु गुप्ता : आज का जवाब तो सुनिये।

उपसभापति : आज की बात आप सुन नहीं रहे हैं और आगे की बात कर रहे हैं। फिर आप बोलेंगे कि मेरी समझ में बात नहीं आ रही है।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: Madam, I said these words intentionally and purposefully because all of us represent certain States. He represents a State. All of us represent States. We have certain obligations towards the States. This House has to show its maturity. Let us on this day not create heat. But let us create light. This is my request to Ram Awadhesh Singhji and others. I am happy to note that he has raised certain points. I will try in my own humble way to dispel those impressions. I was delighted to hear from a person like him the name of Pt. Jawaharlal Nehru who was the architect of modern India. What he gave to us was not only Parliamentary democracy, the system as such, but the first thing he gave was steel and energy as the basis for building the nation. Steel production is a must for the nation. The industrial heart of the nation throbs with the steel industry. Steel, as such, is a dynamic input of the industrial development of the nation. I am aware of all the difficulties that we have gone through. Perhaps Ram Awadheshji and some other Members are also aware what we faced in the first decade of our independence and what we faced in the early or in the mid 50s. Many countries in the world were saying that steel industry is a sunset industry. Even now many countries are saying that steel is a sunset industry. Why? They do not want us to produce steel. They want that they should produce steel and sell it to us. That is why in the 50s Pandit Jawaharlal Nehru took the boldest initiative to have the first steel plant of its kind in the heart of India, that is at Bhilai. Bhilai has its historic importance because Bhilai plant is the first which got support from a socialist country. I respect the burning socialist ideas of Ram Awadhesh Singhji. I must tell him very frankly and in all humility

hat I am more in favour of the public ector than he claims to be. I believe nore in the majesty of the public secor. I don't believe in the propaganda of the public sector as a slogan. But I am in favour of seeing that the public sector becomes the real base for our nation building.

श्री राम अवधेश सिंह : मुंह से आप कह रहे हैं कि पक्ष में है कर्म से उसके खिलाफ है।

उपसभापति : राम अवधेश जी, आप चुप हो जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं चुप हूं।

उपसभापति : आप चुप नहीं हैं। उनको जवाब देने दीजिये। आप जवाब मांग रहे थे अब वो बोल रहे हैं तो आप बीच में कुछ मत कहिये।

श्री राम अवधेश सिंह : सवाल तो मुझे अभी पूछना है।

श्री विश्व बन्धु गुप्ता : अंग्रेजी में बोल रहे हैं आप सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं तो इन से ज्यादा अंग्रेजी जानता हूं, आपको ज्ञान नहीं है। जिस स्कूल में यह पढ़े होंगे उस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूं। मैं अंग्रेजी बोलता नहीं हूं क्योंकि मैं जिस भाषा में वोट मांगता हूं उसी भाषा में यहां बोलता हूं। यह जिस भाषा में वोट मांगते है उस भाषा में नहीं बोलते हैं। यह विदेशी भाषा में बोलते हैं।

उपसभापति : वह जिस भाषा में वोट मांगते हैं आप नहीं सकझेंगे, वह तो कश्मीरी भाषा में वोट मांगते हैं।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: But the difficulty is that he has a different mirror to see and I have a diferent mirror, that is the mirror of this country. I repeat that he sees his own face in a different mirror. I just would like to say that my leader, the Prime Minister, has made a pledge to the country, a pledge to the nation. What is that pledge? That pledge is that India should become a mighty power in the world, that we must build India strong and self-reliant in agriculture, in industry and in front rank technology. This pledge of my leader is being attained by modernising the steel plants. We have two alternatives. I have clearly mentioned very candidly and very frankly that our steel plants have become obsolute. We have two options. Either we close the plants and go in for massive imports or we modernise the plants. We do not want to modernise the way the other countries are modernising. We would like that the conventional technology is replaced by most sophisticated and state-of-art technology. That is the dispute. That is the point. That is why certain people do not give us money for investment in the steel sector. Even now they say that India does not require modernisation by investing in steel. You would not be getting any credit because steel can be imported from the other countries. We have large reserves of iron ore in the country. We are exporting that iron ore. Our desire, our urge, is that we must not only be able to produce steel for our country, but we must be able to export steel.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Export of iron ore is very dangerous for our country.

श्री कपोल देसाई : सुनिये, सुनिये।

उपसभापति : उन्होंने आयरन ओर नहीं कहा, उन्होंने स्टील कहा।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: We will be exporting iron ore to other countries and I must tell you that we are exporting this time also steel and I am awaiting for the day when we shall be one of the major exporters of steel. That is the concept, that is the objective behind modernisation of the steel plants.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR:

What does this modernisation mean? Three things are there. I do not exactly remember whether it was Mr. Ram Awadhesh Singh or some other Member, who asked me a question about the Bhilai Steel Plant, that the original estimate, the approved tender, given to a certain public sector undertaking was only Rs. 900 crores, and how did it go to Rs. 2,500 crores? This was the question that was asked, here in this very House. I do not exactly remember whether he asked the question, or somebody else asked the question.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: I asked the question.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: Perhaps you had asked the question. I did reply that question to your satisfaction. But I feel ashamed if any public sector undertaking, if any public sector enterprise becomes a white elephant. That is the point of difference, that I do not want to make public sector enterprise a while elephant, but I want to make it a race horse (*Interruptions*).

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Would you please yield for a minute?

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: You just listen to me.

उपसभापति : आपने उनको अंग्रेजी बोलने पर तो इन्टयूस कर ही दिया ।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I want to make the public sector enterprise a race horse to compete not only locally but to compete in the world with the most sophisticated technology. For that I require help from outside. I require to improve...

श्री राम अवधेश सिंह : आपने जो बात कही है...

उपसभापति : ये यील्ड नहीं कर रहे हैं।

SHRI MAKHAN LAL FOTED[AR]: I am not yielding. I am not obli[ged to] you.

उपसभापति : आप बैठ जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह : अंत [में] बोलूंगा।

उपसभापति : अंत में कुछ [न]हीं होगा।

श्री राम अवधेश सिंह : ऐसा करिये।

उपसभापति : ऐसा ही करेंगे।

श्री राम अवधेश सिंह : इनका ज[वाब] बहुत कन्ट्राडिक्टरी है, सेल्फ कन्ट्राडिक्[टरी] है।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDA[R]: I want that our public sector un[der]taking should improve its performa[nce]. We have to take a bold step. Wha[t is] that bold step? That is to enhance [the] quality, characteristics of our prod[uc]tion. That means that the quant[ity] of steel is to be increased. The qua[lity] of steel has to be improved. And [it] has to be internationally competiti[ve]. It is my desire that our worker in [the] steel plant should be able to comp[ete] with a worker either in Japan [or] America or in West Germany, that [is] our desire. And I hope that with [the] initiative we are taking, our wor[kers] will be able to compete with anybo[dy] in the world.

The steel industry's development [as] such, some members have said, [and] that the credit does not go to me [or] to the management at the corpora[te] office. The credit goes to the toil a[nd] sweat of the working class who a[re] working there. It has been said [by] some Members that perhaps with m[o]dernisation, we are going to remo[ve] some people.

I have off and on said and emphasised in this House that with modernisation we are not going to make any retrenchment whatsoever. But there has to be improvement in the skill of the workers; they have to be re-trained; they have to be redeployed in plants. That we will do and for that there should be no objection.

Now, coming back to the main issues, whether we have done anything wrong. The hon. Member has raised certain objections. He has compared TISCO with our steel palnts. I must confess and confess very boldly that we have not been able to pay any attention in the past on the maintenance of the plants on purchase of equipment, but TISCO has done this work in a phased manner...

श्री राम अवधेश सिंह: समय दिया जाए, तो मैं बता सकता हूं।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I do not want a running commentary. I had an occasion to visit the TISCO plant and I asked the management there: 'What is you policy? What are you doing?' and they said: Our modernisation started as far back as 1978 and every 3 or 4 years we are investing money. And during the last 10 years they have invested money and they have been able to do it. We could also have invested money at that time. For examp'e, the Visakhapatnam steel plant. We could have taken it up at that time. But there was a naional tragedy in 1977, and from 1977 to 1979 nothing could be done. The country had to be brought back on the rails after 1980. The economy had to be brought back on the rails. That is why there has been cost escalations.

श्री राम अवधेश सिंह: अपना पाप दूसरों के सिर पर डालते हैं। अपना पाप दूसरों पर मत झाड़िये।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: The plant that could have been constructed at a lesser cost at that time, we had to invest more. Now what we have done to make this system cost effctive is, I must tell the hon. Members, I have shed powers. I do not want to make my Ministry or my plant a political empire, as some others had done during 1977—79. We have now transferred the powers. I cannot run a steel plant from the Centre of this House, nor the Chairman SAIL can run it from the corporate office. It is the man at the shop floor whether he is the manager or the deputy manager who has to take the decision, not only for making the plant operational, but he has to take decision for investment.

श्री राम अवधेश सिंह: माडर्नाईजेशन भी उन्हीं का फैसला है।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I say this in the language, the public sector language that we call the memorandum of understanding. The powers that we had or the Ministry had, we have delegated these powers to the plant managers with a view that we fix some targets and they have to remain accountable for completing or for fulfilling those targets. We have given them full autonomy in this regard not only for other things but for even investments. Similarly, in the public sector undertakings, there had been a difficulty. You tender for some work and after one year, the tender will be opened and it may well take you three years to finalise this tender and after three years you can yourself see what would be the cost escalation.

He has referred to MECON. I am happy that he has some good word for Macon as also for Mr. Laha. He must thank us. He was retiring at the age of 58. I requested the Prime Minister that he should be given an extension for two more years. We have not given any extension to the Chairman of the SAIL. His first appointment was for five years and, therefore, he is continuing. I do not want these insinuations to be made by per-

[Shri Makhan Lal Fotedar]

sons who consider themselves responsible.

What we have done is—of course, on the basis of the recommendations of MECON—we have made certain global and indigenous packages. They have said that these things cannot be procured locally. He referred to some multinational. I do not know whether there is any firm in Soviet Union which is a multinational. Some of the works have gone to the Soviet Union. (*Interruptions*)

श्री राम अवधेश सिंह : मल्टी कंसोरशियम तो है न उसमें ? रशिया भी है, जर्मन भी है, ब्रिटिश भी है ।

उपसभापति : राम अवधेश जी, आपसे बहुत विनती है, प्लीज आप चुप बैठे रहिए और भाषण खत्म होने दीजिए ।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I may tell the hon. Member. Of course, it is a consortium between West Germany, and the Soviet Union. But he must thank the Steel Ministry and the Government of India that we have been able to bring the East and the West together for the development of the country. He must thank us for this.

He feels for the Birlas. He has a feeling. It should be a matter of pride for us, for the nation, that these consortiums have chosen the Birlas not as agents but as partners. Indian Parties have got upgraded as partners of foreign consortiums. Not only in India, but many of our industrialists are being asked to come even to the Soviet Union. It is a matter of pride for us that these people are doing it.

Coming back again to the basic issue. About the Memorandum of Understanding, the second thing is, how to improve the system. In the case of Bhilai, he asked how did it go up from Rs. 950 crores to Rs. 2,500 crores. Today, we have to hold somebody responsible if somebody takes up a work for Rs. 100 crores and after five years comes up and says that he has not been able to complete the work within Rs. 100 crores and that it has to be for Rs. 1,000 crores. Then we are left only for conducting a post-mortem. We have now changed the system. We have called this new system 'definitive cost estimates'. I have mentioned in my statement. What is this definitive cost estimate? I do not want to mention the name of the country. Some hon. Member asked about Bokaro. In Bokaro, there is a foreign company. They have not performed well and they have not been able to do the work within the scheduled time. I do not know in what way we should take action. This has cost us much. We have learnt from our own experience and we have learnt from the experience of the developed countries also. This experince is our treasure and this experience is our heritage. We are doing everything on the basis of this experience. I have mentioned about definitive cost estimates. We have given to certain foreign consortia and we have said that they will be held responsible for design, engineering erection and commissioning of the plant on time. Otherwise, they will have to pay the necessary penalty. This commitment is firm. This is one thing. The second is, so far as the local people are concerned, they have to do the work within that stipulated time also. I do not want to criticise any public sector undertaking. I have the experience of the HEC. One of our steel plants in Vizag is being constructed. Day in and day out I and the Minister of Industry have been asking the Managers of those public sector undertakings, "Please supply us the material on time so that we are able to erect it." We have failed in many respects. But in so far as the items which we are importing are such which are not produced in the country, emphatically I would say so. You can ask whether Blast furnace is not being manufactured in India. I will tell the hon. Member, yes, blast furnace is being manufactured and in a plant which

is in his neighbourhood, by the HEC. We are not doing modernisation in the green belt area. We are doing modernisation of the existing plants.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: I know the difference.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: Just allow me to explain. You have used the phrase "Green belt." I am repeating the phrase. We are doing the reconstruction of the blast furnace. That technology is not available indegenously. That technology is not available with the HEC. That technology is not available in any part of the country. And we have to import that technology. That technology is one of the best in the Soviet Union. I think, I should have no objection to import the technology from the Soviet Union.

श्री राम अवधेश सिंह : इसमें कितने करोड़ लगगा ? ... (व्यवधान) ... कितना परसेंट आप इसमें कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I am coming to that. Then I will come to the foreign exchange parts of this Project, I am coming to that. Don't worry.

श्री राम अवधेश सिंह : इसमें खर्चा कितना लगता है ? आखिर देश को जानना चाहिए न ?

उपसभापति : हां, देश जान जाएगा, वह बता तो रहे हैं। आप इतने उतावले क्यों हैं ?

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I would tell the hon. Member that I am told, even the MECON has held and also other metallurgists have told us that reconstruction of blast furnace has never been done in India by any of the companies. I am firmly of the view. My view is based on the opinion given by the MECON and others.

The second thing is, about basic oxygen furnaces, continuous casting and sinter plants, I am told and confirmed by the MECON that no licenced capacity exists in the country. No company makes these plants in the country.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Which plant?

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: These equipments.

Then, about modernisation of rolling mills and raw material handling, no experience in modernising these facilities includng upgradation of technology exists in India. So, per force, we had to import this technology. By importing this technology we are going to adopt this technology also in our country. This has been done on the recommendation made by the MECON because the MECON are our consultants. That also is a public sector undertaking. They are our consultants for the Durgapur Steel Plant.

Then, coming to the foreign exchange component, the MECON prepared the detailed project report or the feasibility report at that time. I agree that is was sanctioned for Rs. 1.357 crores but according to the 1984 or 1986 prices. This plan...

श्री राम अवधेश सिंह : मिकोन की बात मान ली गई है न आपके द्वारा ?

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: We have accepted everything, what MECON has done. It is on the basis of MECON. That is what I am saying, it is on the basis of MECON. It has gone up to Rs. 2,667 crores. According to the present price, estimate it has to be completed within four years and within the definitive cost estimate. They will have no claim whatsoever to ask for any cost escalation at the time when it is completed. I don't want that Bhilai should get repeated in these things. What we have done is that within the stipulated time and within the fixed price

[Shri Makhan Lal Fotedar]

this project has to be completed. We have done two things. Not only the definitive cost estimate, not only the memoranda of Understanding, but another thing for making it more effective is that a separate Executive Director will be in charge of modernisation programme of a plant. He will not be in charge only for erection of the equipment, but he will be in charge even after completion. He has to give us the plant in the best working and operational order, not only immediately after its commission, but even upto three years as a minimum, he has to continue there. He will be personally responsible for this. Otherwise one man used to call for tenders for the equipment of the plant, another man used to construct it, the third man used to commission it and the fourth man used to operate it. We are now holding only are person responsible for all these jobs.

This is how we are trying to make the public sector enterprises reinforced so that they are able to compete in the international market.

Now I come to the point of foreign exchange involved. Total foreign exchange sanctioned is Rs. 685 crores.

SHRI JAGESH DESAI: Out of Rs. 10,000...

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: No. Out of Rs. 2,667 crores, it is only 685 crores for the Durgapur Steel Plant. I am not saying what we have utilised. This has been sanctioned. Then the foreign exchange value for five global packages and foreign exchange estimate value for the sixth global packages are Rs. 546.14 crores and Rs. 40.06 crores respectively. Then foreign exchange value for indigenous packages ordered and estimated is Rs. 25.19 crores. Thus total value of the entire foreign exchange which will go outside the country is Rs. 611.39 crores, though the sanctioned estimate is Rs. 685 crores.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Is it for Durgapur alone?

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: Yes, it is for Durgapur alone. Though the sanction is for Rs. 685 crores, the outflow of Foreign Exchange will be only about Rs. 611 crores. Even in this sanctioned estimate, we have ensured that out of this the hard currency outflow from our country will be only Rs. 390.50 crores and Rupee exchange will be Rs. 167.97 crores. This is to total amount so far as the hard currency is concerned. It will not be more than Rs. 390.50 crores. So, I may tell the hon. Members to see whether we are allowing the hard currency to go out of the country or saving the hard currency. So far as the rupee payment area is concerned, it is the minimum that has been done. For that also there is no hard currency outflow. I feel that this is the cheapest thing that we could have done.

SHRI JAGESH DESAI: And no outflow during subsequent years.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: During the subsequent years nothing. Even a single penny will not go outside the country. The rest will be utilised within the country.

Now, whether A is there or B is there, I told you that I am a votary of the public sector more than anybody else. The policy of our Government is that the public sector shall have commanding heights in our economy.

We shall not and we will not go beyond the Industrial Policy Resolution of 1956.

श्री राम अवधेश सिंह : उसको तो कब का खत्म कर दिया आप लोगों ने, उसके बारे में क्या बोलना। ...

(व्यवधान)

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR : That Resolution is the Magna Carta for us. That Resolution represents the will of the nation.

श्री राम अवधेश सिंह: कहने के लिए नारा देने के लिए यह ठीक है। ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think Mr. Ram Awadhesh Singh should be absolutely satisfied because the Minister almost spoke for an hour.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: Somebody has mentioned about the World Bank. I would not like to involve myself in this World Bank matter; perhaps, the CPM Member is just smiling on this. But you know what is the philosophy of that. I would like to keep silent on that. But one or two things I would like to say. Who is the person who is supposed to take the decisions on this. I must tell you what we have done. We have delegated the authority to various forums or various authorities in the Government what I would call the decision-making process what I would call, who will be responsible for taking decisions in these matters. I will also clarify that. For your information, I want to tell you that the decision-making process about Durgapur steel plant we have very well clarified. The first thing is MECON and the Technical Advisory Committee. The second is the Tender Evaluation Committee in Durgapur steel plant. The third is the Sub-Committee of the SAIL Board. The fourth is the Empowered Committee of Secretaries which shall consist of six Secretaries to the Government of India. They will take the decision on every matter with regard to this. I must tell the hon. Member that the political authority has delegated its powers. I have no reason to disbelieve anyone of them. They are as patriots, the bureaucrats are as patriotic, as any politician or any Member of Parliament. I have no reason to disbelieve anyone of them. This is the Empowered Committee that we have appointed for taking any decision either for allotment of contract or for examining the technological feasibility or any other such matter. Then, there is the Public Investment Board which takes other major decisions. So all these processes have been gone through. Then, what will be the benefit? I will mention only about the benefit that will accrue from the modernization of Durgapur steel plant, so far as techno-economic parameters are concerned. At this time, I will come to the Durgapur Steel Plant because I am keeping my eye on the clock also. Before modernisation, the energy consumption is 11.38 G. Calories per tonne. After modernisation, it will be 8.3 G. Calories per tonne. Then coke rate kg. per tonne of hot metal, before modernisation, is 901 and after modernisation it will be 653. Similarly, blast furnace productivity tonnes per cubic metre per day: before modernisation it is 0.70 and after modernisation it will be 1.04. Similarly, production of the liquid steel before modernisation is 0.986 Million Tones and after modernisation it will be 1.876 Million Tonnes. Similarly, manpower productivity before modernisation is 46 and after modernisation it will increase to 96 It will be more than double. Even TISCO has not been able to... (*Interruptions*)

श्री राम अवधेश सिंह: टोटल कितना मिलियन टन बढ़ रहा है, आप कंपलीट बताइए।

उपसभापति: अगर आप कहेंगे तो सब रिकार्ड आपके घर भेज देंगे।

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I am coming to that. Even the TISCO manpower productivity is not like that even now. I wonder how an ex-socialist can become a votary of TISCO now. I am very happy... (*Interruption*).

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Don't mistake me.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I have the figures about other plants also but I need not go into them and I will give some picture about.... (*Interruptions*) . Then there are other points. Then the hon Member has mentioned that so far as MECON is concerned... (*Interruptions*) .

SHRI RAM AWADHESH SINGH: What about R&D?

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR : R&D is a research organisation. This is not at all involved in these matters. We have built two types of research activity. One is inbuilt in the plant and the other is R&D centre at Ranchi. That has nothing to do with it and they do not make the design for this. For your information, the things that we have given to the foreign companies, not the multinationals, as you called it are the things which we cannot design, procure or manufacture here in the country.

श्री राम अवधेश सिंह : बर्नपुर में किसको दे रहे हैं? कौन कौन से कंसोर्टियम है, उनको बताइए। दुर्गापुर में किसको दे रहे हैं?

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR : I think, I have told the hon. Member even about Burnpur. I have told you that the Japanese are doing it there but investment decision has not been taken so far. They are preparing the DPR... *(Interruptions)*... No, no; that has not been done. They are doing the detailed engineering works. I hope that by the end of the year or by the third quarter of this year, that also will be completed. Similarly we have not taken any investment decision in regard to RSP. So, with these words, I would like to tell the hon. Member that one generally sees one's own face in the mirror. Whatever one's face will be, that will be depicted in that mirror. Our hands are clean. Our intentions are clear and our goal is well-defined. So, with all these things we will take this country to progress and prosperity. Thank you.

श्री राम अवधेश सिंह : मुझे कुछ पूछने दीजिए।

उपसभापति : अब कुछ नहीं पूछेंगे।

श्री राम अवधेश सिंह : बहुत बातें ऐसी कही हैं जिनके बारे में पूछ जरूरी है।

उपसभापति : अब कुछ नहीं पूछ है।

श्री राम अवधेश सिंह : आप परम के खिलाफ काम कर रही हैं।

उपसभापति : परम्परा के खिल नहीं है। आप बैठ जाइये। आपको नहीं है।

श्री राम अवधेश सिंह : इनके जव के बाद हम को पूछने का हक होता है

उपसभापति : आप बैठ जाइये आप परम्परा की बात कर रहे हैं, व नियम है, कोई परम्परा है। जब म जी का जवाब हो जाए तो सवाल पु की न कोई परम्परा है और न व नियम है। आपने पौने घंटे तक भा किया और मंत्री जी ने जवाब दे दि बस हो गया।

श्री राम अवधेश सिंह : एक्सप्लेने पूछने का मौका दिया जाना चाहि

उपसभापति : हम आपकी बात ल्कुल नहीं सुनेंगे। आप बैठ जाइये

श्री राम अवधेश सिंह : स्पष्टीक पूछने दिया जाए।

उपसभापति : इन्होंने जवाब दे दि इससे ज्यादा नहीं दे सकते। आप चि लिखिये यह जवाब दे देंगे।

श्री राम अवधेश सिंह : चिट्ठी क्या मतलब। सदन में बहस हो रही यह सदन को गुमराह कर चले जायें यह कहते हैं कि हमारा हाथ साफ मैं चार्ज लगा रहा हूं कि इनका ह गंदा है। इनको रिजाइन करना चाहि

उपसभापति : आप बैठ जाइ अगर अब आप बोलेंगे तो कोई रि नहीं करेंगे।

श्री राम अवधेश सिंह : यह क्या कह रही है।

उपसभापति : मैं यही कह रही हूं कि अगर अब आप बोलेंगे तो हम रिकार्ड नहीं करेंगे। Nothing will be recorded. I have said it both in Hindi and in English.

आप मेरी अनुमति के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : बहुत स्पष्टीकरण हो गया है। आप बैठ जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : मैंने आप को कहा अब पूछने नहीं दिया जायेगा। मुझे दो जुबानों के अलावा और कोई ऐसी जुबान नहीं आती जो आप समझें। जो कायदा होता है उस लिहाज से आपने सवाल उठाये और मंत्री जी ने हर सवाल का जवाब दिया।

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : मैं यहां बैठ कर दोनों की बातें सुन रही थी और दूसरे लोगों की भी। मंत्री जी ने, जितने सवाल नहीं उठाये गये थे उनसे भी ज्यादा जवाब दे दिया। अगर आप इस पर सटिसफाई नहीं हैं तो मुझे लगता है आपके लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा।

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : ऐसा नहीं होना चाहिए

Please. I have to adjourn the House.

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : आप इस हाउस के शुरू से ही नियम वायलेट कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है हाउस का चेयरमैन साहब ने, जो कुछ आप यहां जिद्द कर रहे थे, हंगामा करते थे उसको सामने रखते हुए आपको इजाजत दे दी। मैंने बहुत सब्र के साथ आपको जितना टाइम आपका था उससे भी ज्यादा टाइम दिया। आप जो चाहा बोले, मंत्री जी को इन्टरप्ट किया, उन पर इल्जाम लगाये और इससे ज्यादा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आप कृपया बैठ जाइये। अब इसके अलावा मंत्री जी कोई जवाब नहीं देंगे मैं आपको भी इजाजत नहीं दूंगी। बहुत हो गया।

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : कालिंग अटेंशन में कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। आप भूल रहे हैं क्योंकि आप इस हाउस में बैठते नहीं हैं खाली शोर मचाते हैं इसलिए कृपया बैठ जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह : *

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I should say, before adjourning the House, that I thank the Members from both sides of the House for their contribution (*Interruptions*).

श्री राम अवधेश सिंह : *

THE DEPUTY CHAIRMAN: I thank all the Members for their co-operation in this current Session which is going to end today. We had long hours of discussion spread over almost 100 hours...

(**व्यवधान**) आप इस तरह से हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। श्री राम अवधेश जी अगर आपको बाहर जाना है तो आप जाइये, मगर शोर मत मचाइये। आपको बोलने की इजाजत

*Not recorded.

[उपसभापति]

दे दी गई और आप बोल भी चुके है। इस लिए अब आप चुपचाप बैठ जाइये ... (व्यवधान) मैंने आपसे कह दिया है. अब आप खामोसी से बैठ जाइये। यह कोई तरीका नहीं है। आपको दुनिया में कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सका है। अब आप बैठ जाइये। मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। आपको समझ नहीं आता है तो आपको कोई नहीं समझा सकता है।

श्री **राम अवधेश सिंह** :*

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Madam, think he is making some serious remarks against the Chair ...(*Interruptions*) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have already said that what he says will not go on record...(*Interruptions*)

अगर आप खामोश नहीं होते हैं तो आपके साथ यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप खामोश नहीं होते हैं और चेयर की रूलिंग को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं तो जो कुछ आपने कहा मैं सब एक्सपंज कर दूंगी।

(*Interruptions*)

आपको अच्छी बात कही है, आप फिर भी नहीं मानते हैं ... **(व्यवधान)**.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Mr. Ram Awadhesh Singh, you must have some consideration for the people who have not taken even their meals... (*Interruptions*) ...They are waiting for the completion of this Calling Attention Motion. This is very unfortunate. It is unfortunate that some Members cannot even listen to the Chair. People will have to go home. Today is the last day of th Session. You have to raise any thing, come with that during the ne: Session. But do not penalise th people who are here now. Don't te the patience of the people...(*Inte: ruptions*)...It is very very unfortu nate...(*Interruptions*)... Don't pen: lise the people.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Le nothing of what he says be recorde

श्री **राम अवधेश सिंह** :*

FAREWELL TO RETIRING MEM BERS AND VALEDICTORY REMARKS

उपसभापति: अब आप बैठ जाइ आखिरी दिन इतना गुस्सा करना ठी नहीं है। चेयरमैन साहब ने आपकी बात मानी, आपको बोलने दिया। मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। अब आप चुपचाप रहिये। कम से कम हाउस का समय तो मत लूटिये। आज आखिरी दिन हम लोगों को स्टाफ को भी शुक्रिया कहना है मेम्बरों को शुक्रिया कहना है। उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया है। खास तौर से आपके इतने लम्बे भाषण को सुना। मंत्री जी ने आपको जवाब दिया आज लास्ट डे है, हम एडजर्न करने वाले हैं। हमारे कुछ मेम्बर रिटायर होने वाले हैं। आप भी उनको शुभकामनाएं देने में शामिल होइये। उनका हाउस में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे बासुमतारी जी रिटायर होने वाले हैं हमारे आसाम के जज साहब रिटायर होने वाले हैं, कुछ और लोग भी रिटायर होने वाले हैं। आपकी वे अच्छी याद लेकर जायें, यह हमें सोचना है। वे क्या सोच कर जाएंगे! अब आप लम्बा चौड़ा भाषण करने के बाद भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आपने कितनी देर लगा दी। इसके लिए आपको शुक्रिया करना चाहिए। सारा स्टाफ बैठा हुआ है।

Honourable Members, I have to mention here that some of the Members' terms are going to expire next month—one is that of Mr. Basumatari

*Not recorded.